

बिहार विधान सभा वादवृत्त

बुधवार तिथि २५ मार्च १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-
विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना में बुधवार, तिथि २५ मार्च १९५० को ११ बजे
पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के समोपतित्व में हुआ ।

गत अधिवेशन के अवशिष्ट प्रश्नों के उत्तर

माननीय श्री श्रीकृष्ण वल्लभ सहाय : महोदय, गत अधिवेशन से रुके हुए शेष
प्रश्नों में से २८ प्रश्नों के उत्तर मेज़ पर रखता हूँ ।

मिशादी संस्थाओं और रांची जिले के आदिम जाति सेवामण्डल द्वारा चलाये
गये संस्थाओं का दी गई अनुदान ।

५९। श्री इगनेश बेरु : क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा
करेंगे कि:—

(क) क्या यह बात सही है कि रांची जिले में अनेक प्राथमिक मिशन पाठशालाएँ
हैं जो पड़ोसे से स्थानिक और सुगल रहने पर भी उनका सरकारी आर्थिक सहायता
नामंजूर की जा रही है, यदि 'हां' तो क्या ?

(ख) क्या आदिम जाति सेवामण्डल के कोई एक भी पाठशाला है, जिसको
ऐसी आर्थिक सहायता सरकार से नामंजूर की गई है, यदि नहीं तो क्या
कारण है ?

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से मिशन पाठशालाओं के निकट ही आदिम
जाति सेवामण्डल ने अपनी पाठशालाओं का खोला है ;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या कोई मिशन
पाठशाला गैर ईसाई आदिवासीयों को अपनी पाठशालाओं में भर्ती करने से इनकार
किया है, यदि हाँ तो उस पाठशाला का नाम और पता ?

महामहिम राज्यपाल के अभिस्ताव पर यह प्रस्ताव किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

३१ मार्च, १९५० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के तृतीय पूरक विवरण के पृष्ठ ९८-१०२ पर की योजना सूची में दिखलाये गये “लोक स्वास्थ्य विभाग” के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिए राज्य शासन को ३३,२९२ रु० तक की पूरक राशि (सप्लिमेंटरी सम) दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिक्षा विभाग EDUCATION

माननीय श्री बट्टीनाथ वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

३१ मार्च, १९५० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के तृतीय पूरक विवरण के पृष्ठ ४३ ८० पर की योजना सूची में दिखलाये गये “शिक्षा विभाग” के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिए राज्य शासन को २,९०,७६,०९१ रु० तक की अनुपूरक राशि (सप्लिमेंटरी सम) दी जाय।

महामहिम राज्यपाल के अभिस्ताव पर यह प्रस्ताव किया जाता है।

Adult (Social) Education : प्रौढ़ शिक्षा

Shri Srish Chandra Banerjee : Sir, I beg to move :

That the Provision of Rs 1,47,720 for 'Adult (Social) Education' be reduced by Re. 1 to discuss advisability or otherwise of the grant.

Sir I beg to draw the attention of Government, through you the fact that this sum is being spent for imposing Hindi on the Bengali-speaking people of the Districts of Manbhum, Singhbhum, Santhal Parganas and Purnea. The demand is so glaringly contradictory and so shamelessly contradictory that it drew the attention of some M. L. C. of Bihar Legislative Council.

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : on a point of order, Sir, कौंसिल के सदस्यों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आप को withdraw कर लेना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष : कौंसिल के सदस्यों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कुछ नहीं कह सकते। आप को इन शब्दों को वापस ले लेना चाहिये।

श्री श्रीचन्द्र बनर्जी : I withdraw.

Sri Sirish Chandra Banerjee : There may be sense in imparting Education in Hindi to the non Hindi-speaking people, but the fact of the matter is that being made on imposition on them. Such a Demand pre supposes two things. One is that there must be in those areas sufficient number of Hindi-speaking communities, and if that be so how did Government Discover them. I may quote with reference to the speeches delivered in this House, I may quote with reference of my hon'ble friend. Mr. Sagar Mahto, who is an elected representative of my District, and who has categorically asserted that his mother-tongue and the mother tongue of his community is Bengali. श्री Nakul Chandra Sahis has also declared in unequivocal terms on the floor of this House that he is a representative of the Harijans and he has also declared that Bengali is truly the Language of the people of those areas. Now, if any referendum is necessary, as I stated the other day, that during the last Satyagrah on this issue that Manbhumi had to take recourse to, out of 206 Satyagrahis 121.....

माननीय अध्यक्ष : शांति-शांति। मुझे मालूम हो रहा है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह असंगत है। इस मांग में हिन्दी पढ़ने वालों के लिए ही इन्तजाम है। बंगला पढ़ने वालों के लिए नहीं। मानभूम, सिंहभूम और संथाल परगना में जो लोग हिन्दी पढ़ना चाहेंगे उनके लिए इस रुपये को खर्च किया जायगा।

SHRI SRISH CHANDRA BANERJEE : I know, Sir, that the grant is being made for the education of the Hindi speaking people of the areas concerned, but the fact of the matter is that there is really vast majority of Bengali speaking people and this I am going to prove.

माननीय अध्यक्ष : शांति शांति। क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हिन्दी बोलने वाले नहीं हैं।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी : जी, हाँ।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : जो लोग अपने लड़कों को हिन्दी पढ़ाना चाहेंगे उनके लिए हिन्दी पढ़ाने का इन्तजाम है।

श्री लम्बोदर मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई श्रीश बाबू को कुछ मिस अण्डर स्टेण्डिंग हो गयी है। इसलिए मैं उन्हें यह समझा देना चाहता हूँ कि जो लोग हिन्दी पढ़ना चाहेंगे उनको हिन्दी अगर पढ़ाया जाय तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। मैं इस विषय में दो चार शब्द आप की आज्ञा से कह देना चाहता हूँ :

माननीय अध्यक्ष : यदि आप को श्री शिरीशचन्द्र बनर्जी अपना वकील मुक-

रैर करें तब बोल सकते हैं ।

SHRI SRISH CHAHDR A BANERJEE: Sir, I am competent to take care of myself what I was going to tell you was that by using power and money on artificial demand for Hindi is being created,

In order to Hindi-ise all these districts which are predominantly Bengali speaking this attempt is being made and it is just thrusting Hindi upon the Bengali-speaking people of the district of Manbhum. I want to show to you, Sir, that the Mahatos, who participated in the Satyagrah movement and whose strength is.....

माननीय अध्यक्ष: मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सत्याग्रह की बात कैसे आ जाती है। यहां तो साफ साफ हिन्दी पढ़ाने के लिए रुपया दिया गया है।

SHRI SRIS CHANDRA BANERJEE: I bow to your ruling, Sir. I want to show that Government is spending money for converting the Bengali speaking people into Hindi-speaking and as Government consider them to be Hindi speaking, but actually they are not I can conclusively prove that there are no communities who are Hindi-speaking.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य की क्या राय है? हिंदी पढ़नेवालों को हिंदी नहीं पढ़ाया जाय।

SHRI SRIS CHANDRA BANERJEE: That is not my point, Sir. Let me say what I have got to say and it there is any irrelevancy in what I say then you are there, sir, on the Chair to stop me. Out of a number of 2067 as many as 121 mahtoo participated in the satyagrah and it is point to consider how they came to participate.

Now, sir, about Adult Education Centres I may tell you that there were 400 such centres running on mediam of Bengali basis up to the end of 1947, But overnight these centres were converted into Hindi centres what was the ground? It would be interesting to hear, sir how could all these 400 adult centres that had been in existance on Bengalee basis up to end of 1947 be converted overnight with the start of 1948 in to Hindi centres what does this signify? can the Hon,ble Education Minister contradict me?

माननीय अध्यक्ष: मैंने अपना फैसला दे दिया है कि आप सत्याग्रह की बात यहां नहीं कह सकते। लेकिन यदि आप बता सकते हैं कि यह रुपया हिंदी भाषी लोगों के लिए खर्च नहीं होना चाहिये, तो ठीक है। लेकिन सत्याग्रह की बात मेरी समझ में यहाँ नहीं आती है। यह असंगत है। शायद कोई दूसरी बात जो यहां नहीं है उसे आप लाना चाहते हैं।

श्री हरिवंशसहाय: यहाँ तो अडल्ट एडुकेशन की बात है।

SHRI SRIS CHANDRA BANERJEE: The result is this. sir. The 400 centres that were being run on Bengali Basis are now going on without any adult pupil. And this is how the money of the Exchequer is being misspent- I can challenge anybody on this issue I am giving facts and nothing but facts.

श्री हरिवंश सहाय: हुजूर ने कहा है कि अडल्ट एडुकेशन अन हिंदी स्पीकिंग पीपुल पर ग्रांट है मगर माननीय सदस्य तो हिंदी स्पीकिंग पीपुल के लिए नहीं बोल रहे हैं। वे तो बंगाली स्पीकिंग के लिए बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: क्या बंगला बोलने वालों के लिए वहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है?

SHRI SRIS CHANDRA BANERJEE: Sir, there are no Hindi-speaking people on community basis in my district. In the meantime they have created an artificial demand for Hindi and pressure is being put upon the Bengal-speaking people to convert them and declare them as Hindi-speaking.

I made 10 allegations against the Bihar Government, s Educational policy showing the Bengali-suppressing activities. of the Government but I received no reply to any one of the allegations. sir, I want a reply to those allegations but I fear that he has no reply to give.

† माननीय श्री ब्रदीनाथ वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त श्रीश बाबू जो प्रश्न उठा रहे हैं यह कोई नयी बात नहीं है। इस हाउस के सभी लोग जानते हैं कि जब जब मौका मिला है, या मौका नहीं भी मिला है, तो ऐसे वक्त में बराबर आप की कोशिश रही है कि मानभूम और बंगला भाषा पर चर्चा किसी न किसी रूप में हाउस में लायी जाय और आप जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं।

उनकी आपत्ति है हिन्दी को बढ़ाने के लिए. हिन्दी बोलने के लिए नहीं। इस तरह की मांग लाकर के हिन्दी का विरोध करने की कोशिश की जाती है। इस ऐसे ही मालूम पड़ती है जैसे अंग्रेज कोई शिकायत करता हो। अंग्रेजी को हटा दो चुकी है। इनका कहना ठीक इसी तरह से है कि जैसे अंग्रेजी के बदले में हिन्दी ठूँसी जाती है। अगर कोई अंग्रेज होता तो यह कहना एक तरह से

† माननीय मन्त्री ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

दुस्त था । मालूम यह होता है कि जैसे पहले से लोग अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, अंग्रेजी ही इनका ओढ़ना बिछौना है । रात को सोते हैं तो अंग्रेजी ही का-स्वप्न देखते हैं । अपनी स्पीच में इन्होंने इसी किस्म की फेना पैदा करने की कोशिश की है । १००-१५० वर्षों से जबर्दस्ती इनके गले के अन्दर अंग्रेजी उतारी गई थी । ठीक इसी तरह आज उनके गले के अन्दर हिन्दी उतारने की कोशिश की जाती है और इसके लिये हर तरह से विरोध करते हैं । मासभूमि में भी ऐसे ही फेजा पैदा की जाती है कि बंगला यहां की जुबान है । सब लोग यहां के बंगला ही बोलते हैं और बंगला ही पढ़ते हैं । यहां के पुराने वासिन्दे महतो, कुरमी और आदिवासी वगैरह हैं, जिनको जबर्दस्ती बंगला बोलना, बंगला पढ़ना सिखलाया गया । अब उनकी तरफ से ये बातें लायी जाती हैं कि ये लोग हिन्दी नहीं चाहते हैं गोया ये लोग मां के पेय से जव पैदा हुए थे तो बंगला ही बोलते हुए पैदा हुए थे । गोया ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि बंगला इन लोगों की मातृभाषा है । यहां संथाली और भुइयां जो हैं वो भी बंगला ही बोलते हुये चले आते हैं और ये सब रीडीकुअस बातें है । ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं । श्रीश बाबू ने यह साबित करने की कोशिश की है कि यहां बंगला के सिवाय हिन्दी पढ़ना बेकार है । लोगों में ऐसी गलत बातावरण पैदा करके बदगुमानी फैलाने की कोशिश की जाती है । लोग यहां के हिन्दी बोलना हिन्दी पढ़ना चाहते थे- इसीलिए यहां हिन्दी के सेण्टर खोले गए । किसी को जबर्दस्ती गोद में उठाकर हिन्दी पढ़ाने के लिए बैठाया नहीं जाता है । वहां के लोगों की स्वाहिश थी कि हिन्दी पढ़ाई जाय । वहां के स्कूलों में काफी तायदाद में हिन्दी पढ़ने के लिए आते हैं । ये कैसे कहा जा सकता है कि जबर्दस्ती बंगला के जगह पर हिन्दी पढ़ाने की कोशिश की जाती है । अगर वे ऐसी बातें कहते हैं तो इसको साबित करने की कोशिश करें । वे कहते हैं कि पुलिस के जरिए वहां हिन्दी पढ़ाई जाती है । मैं चैलेंज करता हू कि वे इस बात को साबित करें । खामखाह लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए । इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं । हिन्दी के खिलाफ उन्होंने काफी प्रोपण्डा करने की कोशिश की है । यहां पर जो रीच दी जाती है उसके एक दिन पहले ही प्रेस भेजकर छपवा दी जाती है । अगर हम गलत कहते हैं तो उनके स्पीच का और जो प्रेस में छपती है दोनों को मिला कर देखें । एक २ लवज उनके स्पीच का उससे मिल जायगा । जो कुछ ये कहते हैं गलत कहते हैं ।

वे कहते हैं कि वहां पर लोग हिन्दी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इतने लड़के हिन्दी पढ़ने के लिए वहां कहां से आ गए । अगर ऐसा न हुआ होता तो स्कूल बन्द हो गया होता । ये खामखाह प्रोपण्डा कर रहे हैं कि वहां बंगाली लोगों का बंगला ही जुबान है और बंगला ही पढ़ना चाहते हैं । अब इसके लिये

ज्यादा जबाब देने की जरूरत नहीं है और न इसके सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत है ।

श्री नकुल चन्द्र शहीश: ये सब पोलिसी के बारे में जो कुछ हो रहा है इसके मुतल्लिक हम साफ तौर से यह कहना चाहते हैं कि वे बिहार सरकार को बंगला पढ़ाने का अधिकार है कि नहीं । हमलोग बराबर ही बंगला पढ़ते आये हैं और बंगला ही हमलोगों का जुबान है इसलिए बंगला पढ़ाने का सरकार को अधिकार है कि नहीं ।

माननीय अध्यक्ष: अधिकार है ।

श्री नकुलचन्द्र शहीश: बंगला, हिन्दी के बारे में इतनी बातचीत हुई है इसका क्या मतलब है ।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रश्न नहीं उठता है । यहां हिन्दी पढ़ने वालों का प्रश्न है । लेकिन स्कूल में बंगला, उर्दू सब पढ़ने का अधिकार है । किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री नकुलचन्द्र शहीश: हमारो जो अंग्रेजी है वो पढ़ना होगा कि नहीं ।

माननीय अध्यक्ष: आपको कौन मना करता है कि आप अंग्रेजी मत पढ़िये । आपको जो २ जी में आये पढ़िये ।

श्री वरियार हेमब्रोम: मैं ये कहना चाहता हूँ कि, जो लोग मानभूमि का प्रोपाण्डा करता है तो वो गलत करता है । हमलोग तो वही भाषा चाहते हैं जो अपने देश की भाषा हो । देश का हिन्दी भाषा बन गया है तो हमलोग वही भाषा पढ़ेंगे । वहां के लोग बंगला पढ़ना चाहते हैं, इस बात को हम हरगिज मानने के बिए तैयार नहीं हैं । हम तो यही चाहते हैं जो हमारी युनिवर्सिटी चाहेगी, हम तो वही करेंगे जो हमारे देश के सब लोग करने हैं । हमारा देश हिन्दी चाहता है तो ठीक है हम हिन्दी ही पढ़ेंगे (वाह वाह) इतना ही हम को कहना है ।

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा: नकुल बाबू ने यह सवाल पूछा है कि हम लोगों को बंगला पढ़ने का अधिकार है या नहीं । तो इस अधिकार को किस ने और कब छीन लिया है आपसे । हमने बताया है कि जबसे भिन्निस्ट्री आयी है, तब से हमलोग चाहते हैं कि हर तरह के लोग जो जुमान चाहें पढ़ सकते हैं, पढ़ें । जितने स्कूल हैं उसमें सब के पढ़ाई के लिए गवर्नमेण्ट से ग्रांट मिलता है । हम चैलेञ्ज करते हैं कि कोई इस बात को साबित करदे कि यह बात

- गलत है। इस बात को बराबर सरकार ने कहा है कि सब को सब जुबान पढ़ने का अधिकार है, इसी तरह बंगला पढ़ने का भी अधिकार है। अगर वहां का सेन्सस लिया जाय तो ५ या ६ परसेंट से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे जिनकी खाहिश है कि बंगला पढ़ें। करीब २ एक सौ स्कूल बिहार में ऐसे हैं जहां बंगला की पढ़ाई होती है। जितना अधिकार उनको इसके लिए मिलना चाहिए उससे ज्यादा अधिकार दिया गया है।

Sri Srish Chandar Banerjee : I am afraid, Sir, I have been misunderstood what I want to say is that this grant is wanted in order to foist hindi language on people who speak bengali language May I know why especially manbhum; Singhbhum, santhal parganas and purnea have been selected for teaching hindi to people living in those places. leaving aside other districts of the province? If the imparting of the language was a necessity, every district of the province should have included. But that has not been done. That shows...

The Hon'ble The Speaker : शांति-शांति। ५ बज गये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं या नहीं?

Sri Sris Chandra Banerjee : I beg to withdraw my motion. My object was to draw this matter to the notice of Government and I have already done this through my speech.

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस हो गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

३१ मार्च, १९५० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के तृतीय पूरक विवरण के पृष्ठ ४३-८० पर की योजना सूची में दिखाए गए 'शिक्षा विभाग' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिए राज्य शासन को २,९०,७६,०९१ रु० तक की अनुपूरक राशि (सप्लिमेण्टरी सम) दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

—:—

उद्योग विभाग: INDUSTRIES

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

३१ मार्च, १९५० का समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के तृतीय पूरक विवरण के पृष्ठ ११५-१२३ पर की योजना सूची में दिखाए गये 'उद्योग विभाग' के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिए राज्य शासन को १०९ रु० तक की